ठाकुर मनमोहन देव और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(और जुड़ी हुई अपील)

(एस के दास, जे एल कपूर, के सुब्बा राव, एम. हिदायतुल्ला और एन. राजगोपाला अयंगर, जे. जे.)

घटवाली कार्यकाल-सरकारी कर्मचारी-की प्रयोज्यता

बिहार भूमि सुधार अधिनियम-विधायी क्षमता-पीठ और विधान का उप रुख-बंगाल विनियमन, 1814 (1814 का विनियमन 29)-बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (1950 का बिहार 30), एस. एस. 2 (o) (q) (r), 23 (1) (f), 3 2 (4)।

अपीलार्थी रोहिणी और पाथरोले घाटवाली नामक घाटवाली कार्यकाल के धारक थे और 1814 के बंगाल विनियमन XXIX द्वारा शासित थे। बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था और 25 सितंबर, 1950 को लागू हुआ था। अपीलार्थियों द्वारा दायर किए गए मुकदमों में यह सवाल उठाया गया था कि क्या अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य उनकी घाटवालियों का अधिग्रहण कर सकता है, उन्होंने दावा किया कि (1) यह अधिनियम रोहिणी और पाथरोले घाटवालियों जैसे सरकारी घाटवालियों के कार्यकाल पर लागू नहीं था, जिन्हें राज्य द्वारा एस के तहत अधिग्रहित नहीं किया जा सकता था। अधिनियम के खंड 3 की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए। 2 और एसएस। 23 (1) (च) और 32 (4), (2) कि अधिनियम का उद्देश्य 1814 के बंगाल विनियम XXIX को निरस्त करना नहीं था और चूंकि उक्त विनियम विशेष कार्यकालों से संबंधित था, इसलिए ऐसे कार्यकालों के संबंध में अधिनियमित विशेष कानून अधिनियम में सन्निहित भूमि सुधारों के संबंध में

सामान्य कानून से प्रभावित नहीं होगा, और (3) कि किसी भी मामले में, घटवाली कार्यकाल, अर्ध-सैन्य प्रकृति के होने के कारण, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टियों । और 2 के तहत आते हैं और इसलिए, अधिनियम राज्य विधानमंडल की क्षमता से बाहर था।

अभिनिर्धारित किया

(1)कि सरकारी घाटवालियों सहित सभी घाटवाली कार्यकाल बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 2 में परिभाषा खंड के भीतर आते हैं और वह धारा। 23 (1) (च) और 3.2 (4), हालांकि वे घटवाली कार्यकाल के प्रश्न पर लागू नहीं हो सकते हैं, अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संचालन से ऐसी कार्यकालों को बाहर करने का प्रभाव नहीं पड़ा।

(2) कि संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम और संविधान की प्रविष्टि 36, सूची II, सातवीं अनुसूची द्वारा कवर किया गया था और इसका सूची । की प्रविष्टियों 1-और 2 से कोई संबंध नहीं था। परिणामस्वरूप, राज्य विधानमंडल अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए सक्षम था।

बिहार राज्य बनाम दरभंगा के महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह और अन्य, (1952) एस. सी. आर. 898, इसके बाद आया।

(3) कि यह सिद्धांत कि विशेष कार्यकाल से संबंधित एक विशेष कानून भूमि सुधारों के बाद के सामान्य कानून से प्रभावित नहीं होता है, उस अधिनियम पर कोई लागू नहीं था जो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित था और 1814 के विनियमन XXIX के निरसन का कोई सवाल ही नहीं उठा था।

राजा सूर्या पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (1952) एस. सी. आर. 1056, आवेदन किया।

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1955 का 273 और 274

1954 के मूल डिक्री संख्या 309 और 310 से अपील में पटना उच्च न्यायालय के 10 दिसंबर, 1954 के फैसले और आदेश से अपील

अपीलार्थियों की ओर से एल. के. झा, जे. सी. सिन्हा, एस. मुस्तफी और आर. आर. बिस्वास।

लाल नारायण सिन्हा, बजरंग सहाय और आरः सी. प्रसाद, उत्तरदाताओं के लिए

1960. 19 सितंबर।

न्यायालय का निर्णय एस. के. डी. ए. एस. जे. द्वारा दिया गया--

पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर ये दो अपीलें उक्त उच्च न्यायालय के 10 दिसंबर, 1954 के फैसले और डिक्री से हैं। उक्त निर्णय और डिक्री द्वारा उच्च न्यायालय ने दो अपीलों को खारिज कर दिया जो दो मुकदमों से उत्पन्न हुईं, शीर्षक मुकदमा सं। 1950 का 42 और 1952 का शीर्षक मुकदमा संख्या 23, जिन पर एक साथ मुकदमा चलाया गया था और जिन्हें देवघर के विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा लागत के साथ खारिज कर दिया गया था।

उन दो मुकदमों के वादी हमारे सामने अपीलकर्ता हैं। अपीलकर्ताओं में से एक ठाकुर मनमोहन देव एक घाटवाली कार्यकाल के धारक थे जिन्हें आमतौर पर रोहिणी घाटवाली के रूप में जाना जाता था, जो संताल परगना जिले में देवगढ़ के उपखंड के भीतर स्थित है। अन्य अपीलार्थी टिकैतनी फलदानी कुमारी भी उसी उप-मंडल में स्थित पाथरोले घाटवाली की धारक थीं। इन दोनों घाटवाली कार्यकालों को पहले बीरभूम घाटवाली के रूप में जाना जाता था और 1814 के बेंगाई विनियमन XXIX द्वारा शासित किया जाता था। वर्ष 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम-1950 (1950 का बिहार अधिनियम 30) अधिनियमित किया गया, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है।

यह अधिनियम 25 सितंबर, 1950 को लागू हुआ। अधिनियम की वैधता को पटना उच्च न्यायालय में कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने उन आधारों पर इसे असंवैधानिक ठहराया था। संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951,18 जून, 1951 को अधिनियमित किया गया था और पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील में, इस न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम दरभंगा के महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह (1) में निर्णय दिया कि यह अधिनियम असंवैधानिक या कथित आधारों पर अमान्य नहीं था, सिवाय इसके कि धारा 4 (बी) और धारा 23 (एफ) के प्रावधानों के संबंध में। इसलिए, अधिनियम की वैधता पर अब उन आधारों पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, हालांकि जिन मुकदमों में से ये दो अपीलें सामने आई हैं, उनमें से एक में यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

दो मुकदमों में मुख्य मुद्दा जो अब बना हुआ है, मुद्दा संख्या 3 है। जिसमें कहा गयाः "क्या बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधान वादी घाटवालियों का अधिग्रहण करने के लिए अभिप्रेत हैं, यदि ऐसा है, तो क्या वे ऐसे घाटवालियों के लिए अपने आवेदन में अधिकार से बाहर हैं इस मुद्दे का निर्णय विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ किया गया था और विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय द्वारा 10 दिसंबर, 1954 के अपने फैसले और डिक्री में अपील पर बरकरार रखा गया था, जिससे ये दोनों अपीलें हमारे पास आई हैं।

अपीलार्थियों की ओर से तीन मुख्य बिंदुओं का आग्रह किया गया है। पहला मुद्दा निर्माण का है और अपीलकर्ताओं का तर्क है कि अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के उचित निर्माण पर, यह रोहिणी और पाथरोले घाटवालियों जैसे घाटवाली कार्यकालों पर लागू नहीं होता है। दूसरा, यह तर्क दिया जाता है कि यदि अधिनियम के प्रावधान अपीलकर्ताओं के घटवाली कार्यकालों पर लागू होते हैं, तो राज्य विधानमंडल इसे लागू

करने के लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि रोहिणी और पाथरोले घटवालियों जैसे घटवाली कार्यकाल अर्ध-सैन्य प्रकृति के थे और यदि अधिनियम उन पर लागू होता है, तो इसे संघ सूची (सूची 1) की वस्तुओं 1 और 2 से संबंधित माना जाना चाहिए और इसलिए, राज्य विधानमंडल की क्षमता से बाहर होना चाहिए. तीसरा तर्क यह है कि अधिनियम का उद्देश्य 1814 के बंगाल विनियमन XXIX को निरस्त करना नहीं है और विशेष कार्यकालों से संबंधित उक्त विनियमन अधिनियम में सन्निहित भूमि सुधारों के संबंध में सामान्य कानून से प्रभावित नहीं होगा। हम इन तीनों दलीलों को उसी क्रम में सुलझाएँगे जिसमें हमने उन्हें कहा है। लेकिन ऐसा करने से पहले, इन घटवाली कार्यकालों की प्रकृति को संक्षेप में समझाना आवश्यक है।

हम यहाँ 1814 के बंगाल विनियमन XXIX के कुछ प्रावधानों को उद्धृत कर सकते हैं। विनियम की धारा 1 में कहा गया है कि बीरभूम जिले में व्यक्तियों के वर्ग द्वारा धारित घाटवाल भूमि एक विशिष्ट कार्यकाल का निर्माण करती है, जिसके लिए मौजूदा विनियमों के प्रावधान स्पष्ट रूप से लागू नहीं होते हैं; इसके बाद यह कहा गया है कि देश के पूर्व उपयोगों और संविधान के अनुसार, इस वर्ग के व्यक्तियों को पीढ़ी दर पीढ़ी, स्थायी रूप से अपनी भूमि रखने का अधिकार है, जो फिर भी बीरभूम के जमींदार को एक निश्चित और स्थापित किराए के भुगतान और सार्वजनिक शांति बनाए रखने और पुलिस के समर्थन के लिए कुछ कर्तव्यों के प्रदर्शन के अधीन है। विनियमन तब घाटवालों के बीच स्थापित व्यवस्था को स्थिरता देने के लिए कुछ नियम निर्धारित करता है और ये नियम एस. एस. में निहित हैं। 2,3,4 और 5। यदि हम एसएस को उद्धृत करते हैं तो यह पर्याप्त होगा। धारा 2,3 और धारा 5 का भाग।

"धारा 2. बीरभूम जिले में घाटवालों के साथ सरकार की ओर से हाल ही में एक समझौता किए जाने के बाद, यह घोषित किया जाता है कि उन्हें और उनके वंशजों को स्थायी रूप से भूमि के कब्जे में रखा जाएगा, जब तक कि वे क्रमशः वर्तमान में उनके

ऊपर निर्धारित राजस्व का भुगतान करेंगे, और वे किराए में किसी भी वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जब तक कि वे समय पर इसका निर्वहन करेंगे और अपने कार्यकाल के अन्य दायित्वों को पूरा करेंगे।

धारा 3. वर्तमान में घाटवाली भूमि को बीरभूम की जमींदारी का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन घाटवाल का किराया सीधे सूरी में तैनात सहायक कलेक्टर या ऐसे अन्य लोक अधिकारी को दिया जाएगा, जिन्हें राजस्व बोर्ड किराया प्राप्त करने का निर्देश दे।

धारा 5. यदि कोई भी घाटवाल किसी भी समय अपने निर्धारित किराए का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकार के लिए यह सक्षम होगा कि वह ऐसे चूककर्ता के घाटवाली कार्यकाल को उसके बकाया की संतुष्टि में सार्वजनिक बिक्री द्वारा बेचा जाए।"

उसी तरह, और उन्हीं नियमों के तहत, जैसे सरकार के पास तुरंत धारित भूमि, या ऐसे चूककर्ता का कार्यकाल किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना जिसे राज्य सरकार बकाया चुकाने की शर्त पर मंजूरी दे; या उसी राजस्व के साथ मूल्यांकन किए गए अनुदानों द्वारा, या बढ़े हुए या कम किए गए मूल्यांकन के साथ, जिसे सरकार पूरा करती प्रतीत हो, इसे हस्तांतरित करना; या इसका ऐसे अन्य रूप और तरीके से निपटान करना जो राज्य सरकार द्वारा उचित समझा जाए। प्रिवी काउंसिल के कई फैसलों में इन कार्यकालों की प्रकृति को समझाया गया है और सत्य नारायण सिंह बनाम सत्य निरंजन चक्रवर्ती (1) में लॉर्ड सुमनर ने इस प्रकार रिपोर्ट के पृष्ठ 198,199 पर स्थिति का सारांश दिया है:

> "संताल परगना में व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए घाटवाली कार्यकाल के तीन वर्ग हैं, (ए) सरकारी घाटवाली, जो सत्तारूढ़ शक्ति द्वारा बनाई गई हैं; (बी) सरकारी घाटवाली, जिन्हें उनके निर्माण के बाद से और आम

तौर पर स्थायी निपटान के समय एक जमींदारी संपत्ति में शामिल किया गया है और जिसमें गठित किया गया है। अपने मूल्यांकन में एक इकाई; और, (ग) जमींदार या उसके पूर्ववर्ती द्वारा बनाई गई और उसकी सहमति से अलग की जा सकने वाली जमींदारी घाटवाली। इन वर्गों में से दूसरा वास्तव में पहली की एक शाखा है। हालाँकि, इस मामले को व्यापक रूप से देखा जा सकता है। अपने आप में घाटवाल एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है समय-समय पर एक विशेष व्यक्ति द्वारा आयोजित एक पद, जो अपने कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य है, जिसके बदले में पदधारी द्वारा आनंद लिया जाना है। इस अर्थ के भीतर स्थितियों की अधिकतम विविधता मौजूद हो सकती है। मजदूरी के लिए रोजगार का केवल एक व्यक्तिगत अनुबंध हो सकता है, जो भूमि के उपयोग या भूमि में एक अचल संपत्ति का रूप लेता है, जो वंशानुगत और स्थायी है, लेकिन कुछ सेवाओं या सेवाओं की मांग पर सशर्त है।कार्यालय सार्वजनिक या निजी, महत्वपूर्ण या उल्टा हो सकता है। थो घाटवाल, दर्रे का रक्षक, आक्रमणकारियों के खिलाफ पूरे देश-पक्ष का गढ़ हो सकता है; वह केवल छोटे लुटेरों के खिलाफ एक प्रहरी हो सकता है; वह एक तरह के खेल रक्षक से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, फसलों को जंगली जानवरों की तबाही से बचाना घाटवेई कर्तव्यों को पुलिस कर्तव्यों और अर्ध-सैन्य कर्तव्यों में विभाजित किया जा सकता है, हालांकि दोनों वर्गों ने अपना बहुत अधिक महत्व खो दिया है, और बाद वाले को किसी भी सख्त रूप में शायद ही कभी प्रस्तुत किया जाता है। फिर से कार्यालय के कर्तव्य ऐसे हो सकते हैं जो उस निर्वहन के लिए व्यक्तिगत क्षमता की मांग करते हैं; दूसरी

ओर, वे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें परोक्ष रूप से निर्वहन किया जा सकता है, शिक्मी कार्यकालों के निर्माण और एक अधीनस्थ बल की नियुक्ति और रखरखाव द्वारा, या वे ऐसे हो सकते हैं जो उनके स्वभाव में केवल थोक में प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट है कि जहां किसी व्यक्ति और उसके उत्तराधिकारियों को घाटवाल के रूप में अनुदान दिया जाता है, या यह माना जाता है कि किया गया है, हालांकि यह तब से खो गया है, घाटवाली सेवाओं का व्यक्तिगत प्रदर्शन तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि अनुदानकर्ता उनके लिए जिम्मेदार है और उन्हें प्राप्त करता है (शिब लाल सिंह बनाम मूरद खान (')). इतना घाटवाल के लिए। वरिष्ठ, जो उसे नियुक्त करता है, हिंदुस्तान के संगठन की अलग-अलग परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर देश पर शासन करने की शक्ति भी हो सकता है, अपनी संपत्ति के भीतर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रथा द्वारा जिम्मेदार भूमि धारक, या केवल निजी व्यक्ति, जिसके लिए एक व्यापक संपत्ति के मामले में पहरेदारों का रखरखाव है, जो एक नियमित कार्यालय के निर्माण की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। यह हमारे सामने विवादित नहीं है कि रोहिणी और पाथरोले घाटवाली सरकारी घाटवाली हैं और यह स्वीकार किया जाता है कि वे 1814 के विनियमन, XXIX द्वारा शासित हैं।"

अब सवाल यह है कि क्या यह अधिनियम इन घाटवालियों पर लागू होता है? अब अधिनियम के कुछ प्रावधानों को पढ़ना आवश्यक है. धारा 2 परिभाषा खंड है, क्ल. (ओ) एक "स्वामी" को परिभाषित करता है, क्ल. (क्यू) एक "कार्यकाल" को परिभाषित करता है और क्ल. (आर) एक "कार्यकाल धारक" को परिभाषित करता है। दो

अभिव्यक्तियों "कार्यकाल" और "कार्यकाल धारक" की परिभाषा को 1954 के बिहार अधिनियम 20 द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से किए गए थे और संशोधन अधिनियम में कहा गया था कि संशोधनों को हमेशा प्रतिस्थापित माना जाएगा। अब, एस के तीन खंड 2(ओ), (क्यू) और {आर) हैं। इन शब्दों में हैं-

"धारा 2 (ओ)-"स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यास में है या जो अपने लाभ के लिए किसी संपत्ति या संपत्ति के हिस्से का स्वामी है, और इसमें उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी शामिल हैं-एक मालिक का हित और, जहां एक मालिक नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग या मूर्ख है, उसका अभिभावक, समिति या अन्य कानूनी संरक्षक।

(क्यू) "कार्यकाल" से किसी कार्यकाल धारक या कम कार्यकाल वाले धारक का हित अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं-(i) एक घटवाली कार्यकाल,

(ii) किसी व्यक्ति के भरण-पोषण के लिए बनाया गया कार्यकाल और जिसे आमतौर पर खरपोष, बाबूआना आदि के रूप में जाना जाता है, और

(iii) कार्यकाल में या उसका हिस्सा, लेकिन इसमें छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम, 1908 के अर्थ के भीतर एक मुंडारी खुंट कट्टीदारी किरायेदारी या छोटा नागपुर कार्यकाल अधिनियम, 1869 के तहत तैयार और पुष्टि किया गया एक भूइनहेरी कार्यकाल शामिल नहीं है।

(r) ""कार्यकाल धारक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी स्वामी या किसी अन्य कार्यकाल धारक से किराया एकत्र करने या उस

पर किरायेदार स्थापित करके उसे खेती के तहत लाने के उद्देश्य से भूमि रखने का अधिकार अर्जित किया है और इसमें शामिल हैं -

(i) ऐसे व्यक्तियों के हित में उत्तराधिकारी जिन्होंने ऐसा अधिकार प्राप्त किया है,

(ii) एक व्यक्ति जो न्यास में ऐसा अधिकार रखता है,

(iii) किसी व्यक्ति के रखरखाव के लिए बनाए गए कार्यकाल का धारक,

(iv) एक घाटवाल और घाटवाल के हित में उत्तराधिकारी, और

(v) जहां एक कार्यकाल धारक नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग का या मूर्ख है, उसका संरक्षक, समिति या अन्य कानूनी संरक्षक।

परिभाषा खंड (क्यू) और (आर) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 'कार्यकाल' में एक घटवाली कार्यकाल शामिल है और कार्यकाल धारक में एक घटवाल और एक घाटवाल के उत्तराधिकारी-हित शामिल हैं। अपीलार्थियों की ओर से तर्क यह है कि परिभाषा खंडों का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि इसमें केवल जमींदारी घाटवालियां शामिल हों, न कि सरकारी घाटवालियां। सबसे पहले, यह इंगित किया जाता है कि (आर) अपने मूल भाग में कहता है कि एक कार्यकाल धारक का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने किसी मालिक या किसी अन्य कार्यकाल धारक से किराया एकत्र करने या उस पर किरायेदार स्थापित करके उसे खेती के तहत लाने के उद्देश्य से भूमि रखने का अधिकार प्राप्त किया है; यह भाग, प्रस्तुत किया गया है, ए पर लागू नहीं हो सकता है। सरकारी घाटवाल, क्योंकि एक सरकारी घाटवाल किसी मालिक या किसी अन्य कार्यकाल से अधिग्रहण नहीं करता है. धारक को उसमें उल्लिखित दो उद्देश्यों में से किसी के लिए भी भूमि रखने का अधिकार है। इस संबंध में हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया

गया है कि (ओ) जो एक स्वामी को परिभाषित करता है और यह आगे बताया गया है कि, जैसा कि लॉर्ड सुमनर ने कहा है, सरकारी घाटवाल या तो शासक शक्ति द्वारा बनाए गए थे या उनके निर्माण के बाद से थे और आम तौर पर स्थायी निपटान के समय एक जमींदारी संपत्ति में शामिल किए गए थे और इसके मूल्यांकन में एक इकाई के रूप में गठित किए गए थे। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि सरकारी घाटवालियों ने किसी मालिक या किसी अन्य कार्यकाल धारक से कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया था। दूसरा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि (क) के उप-(क) और उप-(iv) को दोनों खंडों के मूल भाग के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, भले ही उपखंड स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि एक कार्यकाल में एक घटवाली कार्यकाल शामिल है और एक 'कार्यकाल धारक' में एक घाटवाल शामिल है। यह इंगित किया गया है कि एक जमींदारी घाटवाल एक मालिक से अपना हित प्राप्त करता है और खंड (क) और (र) का मूल भाग एक जमींदारी घाटवाल और उसके कार्यकाल पर लागू हो सकता है, लेकिन दोनों खंडों का मूल भाग सरकारी घाटवाल और उसके कार्यकाल पर लागू नहीं हो सकता है। हम इस तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं।

जहां कानून स्पष्ट शब्दों में कहता है कि 'कार्यकाल' अभिव्यक्ति में एक घाटवेली कार्यकाल शामिल है और 'कार्यकाल धारक' अभिव्यक्ति में घाटवाल और घाटवाल के हित में उत्तराधिकारी शामिल हैं, दोनों अभिव्यक्तियों के आयाम को कम करने के लिए मजबूर करने वाले कारण होने चाहिए। बिहार विधानमंडल को सरकारी घाटवालियों और जमींदारी घाटवालियों के बीच के अंतर के बारे में पता होना चाहिए और अगर इरादा सरकारी घाटवालियों को बाहर करने का होता, तो दो परिभाषा खंडों में यह कहने से आसान कुछ नहीं होता कि उनमें सरकारी घाटवालियों को शामिल नहीं किया गया था। इसके विपरीत, विधायिका ने सरकारी घाटवालियों और जमींदारी घाटवालियों के बीच कोई अंतर नहीं किया, लेकिन सभी घाटवाली कार्यकालों को परिभाषा खंडों के भीतर

शामिल किया। परिभाषा खंडों में कोई प्रतिबंधात्मक शब्द नहीं हैं और हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि उनमें किसी भी प्रतिबंध को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि दो परिभाषा खंड पहले मूल भाग में बताते हैं कि दोनों अभिव्यक्तियों का सामान्य अर्थ क्या है, और फिर कहते हैं कि अभिव्यक्तियों में अन्य बातों के साथ-साथ एक घटवाली कार्यकाल और एक घाटवाल और एक घाटवाल के हित में उत्तराधिकारी शामिल होंगे। इस प्रकार, दो परिभाषा खंडों को कृत्रिम रूप से विस्तारित किया गया है ताकि सभी घटवाली कार्यकाल और सभी घाटवाल और उनके उत्तराधिकारियों को शामिल किया जा सके, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या वे दो खंडों के मूल भाग में बताए गए सामान्य अर्थ के भीतर आते हैं। खंड (आर) के उपखंड (वी) और खंड (क्यू) के उपखंड (iii) से भी दो परिभाषा खंडों का ऐसा कृत्रिम विस्तार स्पष्ट है। खंड (क्यू) का उपखंड (iii) परिभाषा खंड से कुछ कार्यकालों को बाहर करता है जो अन्यथा 'कार्यकाल' अभिव्यक्ति के सामान्य अर्थ के भीतर आते हैं और खंड (आर) का उपखंड (वी) संरक्षक समितियों और क्यूरेटरों के लिए 'कार्यकाल धारक' अभिव्यक्ति का विस्तार करता है। जब हम इस प्रकार की कृत्रिम परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि "अर्थ और इसमें आदि शामिल होंगे", तो इस तर्क के लिए कोई जगह नहीं है कि भले ही परिभाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि कुछ किसी विशेष अभिव्यक्ति के भीतर शामिल है, लेकिन इसे इस कारण से बाहर रखा जाना चाहिए कि यह उस अभिव्यक्ति के सामान्य अर्थ के भीतर नहीं आता है।

अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने इस तर्क के समर्थन में अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया है कि अधिनियम सरकारी घाटवालियों पर लागू नहीं होता है। उन्होंने एस का उल्लेख किया है। अधिनियम की धारा 23 (1) (च) और धारा 32 (4)। धारा 23 खंड (ए) से (एफ) में उल्लिखित प्रत्येक स्वामी या कार्यकाल धारक की सकल संपत्ति से कुछ राशियों की कटौती करके

क्षतिपूर्ति मूल्यांकन-सूची तैयार करने के उद्देश्य से शुद्ध आय की गणना से संबंधित है। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि जो पहले धारा 23 (1) धारा का खंड (जी) था वह अब खंड (एफ) बन गया है, क्योंकि धारा 23 (1) के मूल खंड (एफ) को इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य बनाम दरभंगा के महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह (') में असंवैधानिक ठहराया गया था। धारा 23 (1) जहाँ तक हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है :

> "धारा 23 (1) क्षतिपूर्ति निर्धारण सूची तैयार करने के उद्देश्य से, किसी स्वामी या कार्यकाल धारक की शुद्ध आय की गणना, यथास्थिति, ऐसे स्वामी या कार्यकाल धारक की सकल संपत्ति में से निम्नलिखित की कटौती करके की जाएगी, अर्थात्ः - (ए.)...
>
> (बी)...
>
> (सी)...
>
> (डी)...
>
> (ई)। ..
>
> (f) ऐसी संपत्ति या कार्यकाल के संबंध में देय कोई अन्य कर या कानूनी अधिरोपण जिसका खंड (क) से खंड (ङ) में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है या किसी अन्य रूप की सेवाओं या दायित्वों का मूल्य, जो निर्धारित तरीके से परिवर्तित किया जाना है, जो ऐसी संपत्ति या कार्यकाल के उसके आनंद के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त के रूप में प्रदान या निर्वहन किया जाना है।"

अब, हमारे सामने तर्क यह है कि धारा 23 (1) का खंड (च) किसी सरकारी घाटवाई पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे अभी भी उन सेवाओं और दायित्वों का पालन

करने के लिए कहा जा सकता है जो उसने अपने पद के कारण किए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम का उद्देश्य घटवाली कार्यालय को समाप्त करना नहीं है और चूंकि कार्यालय और कार्यकाल अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए खंड (च) में निर्दिष्ट गणना सरकारी घटवाली के मामले में नहीं की जा सकती है। हमारा ध्यान पटना उच्च न्यायालय के बाद के फैसले की ओर भी आकर्षित किया गया है। 20 मार्च, 1959 का 7 और 1958 का 8), जिसमें अधिग्रहण और घाटवाली कार्यकाल को फिर से शुरू करने और इस तर्क के बीच अंतर किया गया था कि घाटवाली कार्यकाल के अधिग्रहण पर समाप्त कार्यालय को स्वीकार नहीं किया गया था। हमें बार में सूचित किया गया है कि निर्णय इस न्यायालय में अपील के तहत है, इसलिए हम उसमें व्यक्त किए गए विचार की शुद्धता या अन्यथा के बारे में कुछ भी कहने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। यह इंगित करना पर्याप्त है कि यह मानते हुए कि अपीलकर्ताओं का तर्क सही है और धारा 23 (1) का खंड (च) लागू नहीं होता है, यह आवश्यक नहीं है कि अपीलकर्ताओं के घटवाली कार्यकाल को अधिनियम की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धारा 23 (1) (च) शुद्ध आय की गणना करने के उद्देश्य से केवल कार्यकाल धारक की सकल संपत्ति 6 से किसी विशेष वस्तु की कटौती का प्रावधान करती है। भले ही खंड (च) लागू नहीं होता है, कानून खंड (क) से (ङ) में उल्लिखित अन्य कटौती का प्रावधान करता है। वे खंड निर्विवाद रूप से एक घटवाली कार्यकाल पर लागू होते हैं और उनके आधार पर एक क्षतिपूर्ति मूल्यांकन-सूची तैयार की जा सकती है। यह कहना सही नहीं होगा कि क्योंकि सरकारी घटवाली के मामले में कटौती की कोई विशेष वस्तु लागू नहीं होती है, इसलिए इस तरह के घटवाली कार्यकाल को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण धारा 23 की योजना के साथ असंगत होगा। धारा 23 की योजना यह है कि शुद्ध आय की गणना करने के लिए कुछ कटौती की जानी चाहिए। कुछ वस्तुएँ एक मामले में लागू हो सकती

हैं और कुछ लागू नहीं हो सकती हैं। इस धारा में यह विचार नहीं किया गया है कि सभी मदें प्रत्येक स्वामी या कार्यकाल धारक के मामले में लागू होनी चाहिए।

हम-अब धारा 32 पर आते हैं। एक्ट करें। धारा 32 (4) में कहा गया हैः

> "धारा 32 (4) यदि वह संपत्ति या कार्यकाल जिसके संबंध में मुआवजा देय है, एक सीमित मालिक या जीवन-ब्याज धारक के पास है, तो मुआवजा अधिकारी मुआवजे की राशि जिले के कलेक्टर के पास जमा करेगा और कलेक्टर सीमित मालिक या जीवन-ब्याज धारक को उसके जीवनकाल के दौरान मुआवजे की राशि पर उपार्जित ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देगा। ऐसी राशि तब तक कलेक्टर के पास जमा रहेगी जब तक कि इस उप-धारा के परंतुक के तहत भुगतान करने के बाद मुआवजे की राशि या उसके हिस्से की राशि, यदि कोई हो, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाती है जो इसके लिए पूरी तरह से हकदार हैः
>
> बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात किसी सीमित मालिक या जीवन ब्याज धारक के किसी भी कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी खर्च को चुकाने के लिए मुआवजे की राशि के एक हिस्से के भुगतान के लिए जिला न्यायाधीश को आवेदन करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करती है।"

यह तर्क दिया जाता है कि धारा 32 की उप-धारा (4) सरकारी घाटवाली पर भी लागू नहीं होती है, क्योंकि उसमें आने वाली सीमित स्वामी अभिव्यक्ति का उपयोग उस अर्थ में किया गया है जिसमें इसे हिंदू कानून में समझा जाता है और सरकारी घाटवाली का धारक उस अर्थ में सीमित मालिक नहीं है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने अपने

इस तर्क के समर्थन में कि 'सीमित स्वामी' अभिव्यक्ति का हिंदू कानून में तकनीकी अर्थ है, उप-धारा (4) के परंतुक में आने वाली 'कानूनी आवश्यकता' अभिव्यक्ति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। प्रत्यर्थी राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि 'सीमित मालिक' और कानूनी आवश्यकता 'अभिव्यक्तियों का उपयोग किसी भी तकनीकी अर्थ में नहीं किया जाता है और यह उन व्यक्तियों पर लागू हो सकता है जो उन शर्तों के तहत इसे अलग या विभाजित नहीं कर सकते हैं जिन पर वे कार्यकाल रखते हैं। यहाँ फिर से हम धारा 32 की उप-धारा (4) के वास्तविक दायरे और प्रभाव पर उच्चारण करना अनावश्यक समझते हैं। हमारे सामने छोटा सवाल यह है कि क्या सरकारी घाटवालियों को धारा 32 की उप-धारा (4) के कारण अधिनियम से बाहर रखा गया है? आइए हम बिना निर्णय लिए मान लें कि उप-धारा (4) घटवाली कार्यकाल पर लागू नहीं होती है। इसका क्या परिणाम होता है? धारा 32 केवल मुआवजे के भुगतान के तरीके का प्रावधान करती है। यदि उप-धारा (4) लागू नहीं होती है, तो मुआवजे का भुगतान उप-धारा के अनुसार करना होगा। धारा 32 का (1) जो कहता है-

> "धारा 32 (1)। जब वह समय जिसके भीतर किसी क्षतिपूर्ति निर्धारण-सूची में किसी प्रविष्टि या चूक के संबंध में धारा 27 के तहत अपील की जा सकती है, समाप्त हो गई है या जहां उस धारा के तहत ऐसी कोई अपील की गई है और उसका निपटारा कर दिया गया है, तो क्षतिपूर्ति अधिकारी उन मालिकों, कार्यकाल धारकों और अन्य व्यक्तियों को, जो मुआवजे के हकदार होने के लिए धारा 28 के तहत अंत में प्रकाशित ऐसी क्षतिपूर्ति-सूची में दिखाए गए हैं, धारा 4 के खंड (सी) के तहत या इस तरह से कटौती की जाने वाली किसी अन्य धारा के तहत कलेक्टर द्वारा आदेशित किसी भी मुआवजे की राशि से

> कटौती करने के बाद उक्त सूची के संदर्भ में उन्हें देय मुआवजे का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ेगा।
>
> इसलिए, परिणाम यह नहीं है कि सरकारी घाटवाली अधिनियम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उप-धारा (4) लागू नहीं होती है। परिणाम यह होगा कि इस तरह के कार्यकाल के धारकों को अलग तरीके से मुआवजा दिया जाएगा। घाटवाली कार्यकाल में मालिकाना हित रखने वाले अन्य लोगों को मुआवजे की राशि के खिलाफ क्या अधिकार हैं, यह यहां निर्णय के लिए नहीं आता है।"

इसलिए, हमारा विचार है कि न तो धारा 23 (1) (च) और न ही धारा 32 (4) में अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया आवश्यक और अपरिहार्य परिणाम है, अर्थात, अपीलकर्ताओं के घटवाली कार्यकाल को अधिनियम के संचालन से बाहर रखा जाना चाहिए, भले ही परिभाषा खंडों में उन्हें स्पष्ट रूप से शामिल किया गया हो।

यह हमें दूसरे बिंदु पर लाता है जो हमारे सामने रखा गया है। उस बिंदु को बहुत जल्द निपटाया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि अधिनियम के प्रावधान सरकारी घाटवालियों पर लागू होते हैं, तो अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से उतना ही बाहर हो जाता है जितना कि अधिनियम तब संघ सूची की वस्तुओं 1 और 2 के संबंध में कानून बन जाता है। ये दो चीज़ें हैं -

> "1. भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसमें रक्षा की तैयारी और ऐसे सभी कार्य शामिल हैं जो युद्ध के समय में इसके अभियोजन के लिए और इसकी समाप्ति के बाद प्रभावी विमुद्रीकरण के लिए अनुकूल हो सकते हैं।

> 2. नौसेना, सैन्य और वायु सेना; संघ के किसी भी अन्य सशस्त्र बल।"

हम समझते हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस अधिनियम का भारत की रक्षा या संघ के सशस्त्र बलों से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि लॉर्ड सुमनर ने 1923 में बताया था, हालांकि घटवाली कर्तव्यों को पुलिस कर्तव्यों और अर्ध सैन्य कर्तव्यों में विभाजित किया जा सकता है, दोनों वर्गों ने अपना महत्व खो दिया था और बाद वाले की शायद ही कभी मांग की गई थी। इस न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम महाराजा धीरज (1) दरभंगा के सर कामेश्वर सिंह और अन्य मामलों में टिप्पणी की थी।

> "हालाँकि, मेरी राय में, इस विधान का सार और सार राज्य सरकार को संपदाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण है और यह सूची II के विधायी शीर्ष प्रविष्टि 36 के दायरे में आता है। कानून के ढांचे के भीतर भूमि सुधार की कोई योजना नहीं है, सिवाय इसके कि एक पवित्र आशा व्यक्त की जाती है कि आयोग इसे प्रस्तुत कर सकता है। बिहार विधानमंडल निश्चित रूप से संपदाओं के हस्तांतरण के विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम था और इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में अधिनियम संवैधानिक है।
>
> हमारा मानना है कि शुष्क सार में कानून को सूची II की मद 36 द्वारा कवर किया गया था (जैसा कि यह तब था) और इसका सूची I की मद I और 2 से कोई संबंध नहीं है।"

अब, 1814 के विनियमन XXIX पर स्थापित अंतिम तर्क के रूप में। हमारे विचार में संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम और इसके परिणामस्वरूप 1814 के विनियमन XXIX के निरसन का कोई सवाल ही नहीं उठा और न ही इस सिद्धांत पर

विचार करना आवश्यक है कि विशेष कार्यकालों से संबंधित एक विशेष कानून भूमि सुधारों के बाद के सामान्य कानून द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इस सिद्धांत का वर्तमान मामले में कोई उपयोग नहीं है। अधिनियम में स्पष्ट रूप से सभी घटवाली कार्यकालों को इसके दायरे में शामिल किया गया है और धारा 3 के तहत एक अधिसूचना जारी करने पर बिहार राज्य में सभी अधिकारों को निहित करने का प्रावधान है और धारा 4 के तहत ऐसी अधिसूचना जारी करने पर कुछ परिणाम सामने आते हैं, इसके बावजूद कि कुछ भी निहित है जो उस समय के लिए कोई अन्य कानून है। यह ध्यान देने योग्य है कि बंगाल स्थायी निपटान विनियमन, 1793 (बंगाल 1793 का विनियमन I), अन्य स्थायी रूप से बसे हुए संपदाओं के अधिग्रहण के रास्ते में नहीं खड़ा था, और यह देखना मुश्किल है कि 1814 का विनियमन XXIX घाटवाली कार्यकालों के अधिग्रहण के रास्ते में कैसे खड़ा हो सकता है। राजा सूर्या पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (') मामले में इस न्यायालय के फैसले में वास्तव में इस बिंदु को शामिल किया गया है, जहां यह कहा गया थाः

> "क्राउन किसी विधायिका को अपने विधायी अधिकार से केवल इस तथ्य से वंचित नहीं कर सकता है कि अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए वह उस क्षेत्र के भीतर भूमि का अनुदान देता है जिस पर ऐसा विधायी प्राधिकरण मौजूद है और कोई भी अदालत अपनी संप्रभु क्षमता के वैध दायरे में काम करने वाले बिहार विधान निकाय के अधिनियम को रद्द नहीं कर सकती है। यदि, इसलिए, यह पाया जाता है कि क्राउन अनुदान का विषय प्रांतीय विधानमंडल की क्षमता के भीतर है, तो कुछ भी उस विधानमंडल को इसके बारे में कानून बनाने से नहीं रोक सकता है, जब तक कि संविधान अधिनियम स्वयं इस

विषय पर कानून को पूरी तरह से या सशर्त रूप से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है।"

ऊपर दिए गए कारणों से, हम मानते हैं कि अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किए गए तीन बिंदुओं में से किसी में भी कोई सार नहीं है। अपील विफल हो जाती हैं और लागत के साथ खारिज कर दी जाती हैं; केवल एक सुनवाई शुल्क होगा।

अपील खारिज कर दी गई।